# चुनाव सुधार के लिए पाकिस्तानी ने भारतीय वकील से माँगी मदद

Ashwini Upadhyay
to kslaw1, bcc: Akanksha, abhi...
11:38 View details

ɔther Khurram,

y happy that you are striving for elec
n Pakistan through the Supreme Co

il you my petitions on electoral refo
arge any fee for this but I expect a p

चुनाव प्रक्रिया में सुधार को लेकर अब पाकिस्तान भी भारत से सीख लेने लगा है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर कर मांग की है कि नेताओं के एक साथ दो सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। अब पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने अश्विनी उपाध्याय से इसी तरह की याचिका अपने यहां दायर करने को लेकर संपर्क साधा और मदद मांगी है। खास बात यह है कि अश्विनी उपाध्याय तुरंत इसके लिए राजी हो गए और वे बिना किसी शुल्क के संबंधित सामग्री पाकिस्तानी वकील को उपलब्ध करवा रहे हैं। मालूम हो, 25 जुलाई को पाकिस्तान में आम चुनाव है।

पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के वकील खुर्रम सईद ने 13 जून को अश्विनी उपाध्याय को इस संबंध में ईमेल किया। सईद ने लिखा- 'मैं भी पाक सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह की याचिका दायर करना चाहता हूं और रिसर्च के दौरान आपके द्वारा फाइल की गई याचिका के बारे में पता चला। आप चुनाव, राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में प्रभावी तथा चुनौतीपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। मैं आपकी कामयाबी की दुआ करता हूं।'

सईद ने आगे लिखा – 'मैं चाहता हूं कि इसमें आप मेरी मदद करें। यदि आप अपनी याचिका की एक प्रति मुझे देते हैं और इस पर कोर्ट में सरकार द्वारा किए गए कमेंट्स बताते हैं तो यह बहुत बड़ी मदद होगी। मैं आपसे मेहनताने की बात तो नहीं करता, लेकिन किस तरह से इसकी कीमत चुका सकता हूं, यह जरूर बताएं।'

सईद ने यह भी लिखा है कि, 'मैं पाकिस्तान में एक और केस दायर करने जा रहा हूं, जिसमें मांग की जाएगी कि नेता चुनाव प्रचार के दौरान जो वादे करते हैं, उन्हें पूरे करें। यदि चुनाव जीतने के बाद वादे पूरे नहीं कर पाते हैं, तो उनका निर्वाचन रद्द माना जाए। यदि भारत में इस संबंध में कोई कानून है, तो उसका इनपुट भी मेरे लिए बहुत उपयोगी होगा।'

अपने ईमेल के आखिरी में सईद ने अपना मोबाइल नंबर भी दिया। वहीं इसका जवाब लिखते हुए अश्विनी उपाध्याय ने खुशी जाहिर की कि सईद सुप्रीम कोर्ट के जरिए अपने मुल्क में चुनाव सुधार लाना चाहते हैं।

अश्विनी ने लिखा- 'मैं आपको अपनी याचिकाओं की कॉपी ईमेल कर दूंगा और इसके बदले मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंध बने रहें।'